

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर, राजस्थान

क्रमांक: डीसी/विधि/2014/82

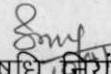
दिनांक :- 10-04-2014

प्रभारी, सर्वर रूम,  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :-प्रकरण संख्या 383/11 सरकार बनाम मदन लाल सुमन, आत्मज  
गेंदीलाल सुमन निवासी सुल्तानपुर रोड, ग्राम-पोस्ट, दीगोद जिला कोटा  
मे पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने  
बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5  
कोटा ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 12.03.2014 को आदेश पारित किया है जिसकी  
प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त  
औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई-मेल भी करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (9)

  
औषधि नियंत्रक  
राज0 जयपुर

2015

26/3

14/3/14

नमल प्रिण्टि  
14/3/14

पीठासीन अधिकारी  
नं०फौ०स० 383/11

सोनिया बेटीवाल  
29 MAR 2014

सरकार  
बनाम

मदनलाल सुमन आत्मज गेंदीलाल जाति सुमन निवासी सुल्तानपुर रोड, ग्राम...  
जिला कोटा

अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b) (ii), 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम  
1940

उपरिथत - स०लो०अ०  
श्री महेन्द्र स्वरूप भार्गव, अधिवक्ता मुलजिम

निर्णय दिनांक 12-3-95

इस प्रकरण का परिवाद औषधि निरीक्षक श्री डा० मनोज कुमार...  
मदनलाल सुमन के विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा में अपराध अन्तर्गत धारा  
18(c) एवं 18 (A) दण्डनीय अपराध अन्तर्गत धारा 27(b) ii एवं 28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री  
अधिनियम 1940 का दिनांक 26-2-98 को पेश किया। इसके पश्चात यह प्रकरण अपर मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगा) कोटा को अंतरित किया गया। इसके  
पश्चात यह प्रकरण पुनः माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा के आदेश दिनांक  
28-5-11 द्वारा इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

अभियोगी डा० मनोज कुमार त्रिपाठी, औषधि निरीक्षक, कोटा ने परिवाद में अंकित किया  
है कि वह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 21 के तहत समस्त राजस्थान  
राज्य के लिए विधिवत निरीक्षक नियुक्त है जिसकी अधिसूचना राज० पत्र अंक... 1985...  
(क) में संस्था प० 26 (10) एम०ई० 1 गुप - 1 1 75, जयपुर दिनांक 20 जुलाई 1985...  
प्रदर्शित हो चुकी है, जिसके अनुसार प्रार्थी अधिनियम की धारा 32 के तहत न्यायालय  
अभियोग लाने हेतु प्राधिकृत है। अभियोगी ने दिनांक 28-2-95 को डा० जो०पी० माधु  
तत्कालीन संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, कोटा एवं डा० के०एल० कुमठ एवं  
अन्य दो स्थानीय साक्षीगण की उपस्थिति में अभियुक्त की दुकान का निरीक्षण किया, जिसमें  
औषधियों का स्टॉक पाया गया, जिसको अभियुक्त ने स्वयं द्वारा बेचने हेतु रखा जाना बताया एवं  
औषधियों के संग्रहण एवं विक्रय हेतु कोई अनुज्ञाप नहीं पाया गया, नही रजिस्टर्ड मेडिकल  
प्रेक्टिशनर का प्रमाण पत्र पेश कर सका। फर्द रिपोर्ट तैयार की गयी, मुलजिम एवं मनोज  
व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये-। अभियुक्त से फार्म नंबर 16 में अंकित 9 प्रकार की औषधियों  
जब्त की गयी एवं फर्द रिपोर्ट एवं जब्ती रसीद फार्म नंबर 16 की प्रति अभियुक्त को दी गयी।  
अभियोगी ने दिनांक 4-3-95 को श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा के समक्ष  
अभियुक्त से जब्तशुदा औषधियों के बारे में सूचना दी एवं फर्द रिपोर्ट, सामग्री एवं प्रमाण  
सत्यापित प्रति पेश करते हुए कस्टडी आर्डर प्राप्त करने बाबत निवेदन किया जिस पर श्रीमान  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा ने सीलशुदा पेकिट को अभियोगी की सुरक्षा में रखने के निदेश  
प्रदान किये। उक्त कार्यवाही एवं जांच आदि की सूचना जरिये पत्र क्रमांक 497 दिनांक  
23-3-95 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को दी गयी क्योंकि मदनलाल ने स्वयं  
को ग्राम नयागाँव अहीरान जिला कोटा में स्थित उच्चीकृत उप केन्द्र में प्रभारी मेल नर्स के पद  
पर कार्यरत होना जाहिर किया था एवं अभियुक्त की दीगाद स्थित निजी दुकान में जब्तशुदा



03.14  
न्यायाधीश  
कोटा (राज.)  
प्रतिलिपि  
22  
29 MAR 2014

21.12.14  
अभियुक्त अधिवक्ता  
कोटा (राज.)

औषधियों में राजकीय सप्लाई की औषधियाँ भी थी। मेलनर्स ग्रेड सेकिण्ड के अपोइंटिंग एण्ड रिमुवल आथेरिटी, एडीशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विस के तहत है। इनकी अपोइंटिंग एण्ड रिमुवल आथेरिटी, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार नहीं है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में भी किसी पूर्व स्वीकृति का भी प्रावधान नहीं है। ग्राम दीगोद में अभियुक्त की दुकान चलने से अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन हुआ है। वह उनके उनके राजकीय निर्वहन में भी नहीं आता है। अतः चालानी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अभियोगी ने अभियुक्त को जरिये पत्र क्रमांक 415-17 दिनांक 11-12-97 में अधिनियम के प्रावधानों में नोटिस देकर जवत्शुदा औषधियों के बिल आदि बताने का निर्देश दिया, जिसके जवाब में मुलजिम ने पत्र दिनांक 21-12-97 द्वारा जाहिर किया कि औषधियाँ कय बिल आदि प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं एवं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर का प्रमाण पत्र तथा औषधियों का अनुज्ञापत्र भी पेश नहीं किया। औषधि नियंत्रक राज० जयपुर ने प्रकरण में पत्र क्रमांक 17 दिनांक 21-2-98 द्वारा अभियोगी को अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में वाद पेश करने हेतु अभियोजन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त ने बिना औषधि अनुज्ञापत्र के 9 प्रकार की औषधियों का संग्रह कर एवं विक्रयार्थ विस्तारण हेतु प्रदर्शित करके अधिनियम की धारा 18 (c) का उल्लंघन किया है जो धारा 27(b) ii के तहत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त ने धारा 18 (A) के तहत औषधि निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर औषधियों को जिस व्यक्ति से कय किया/प्राप्त किया का नाम एवं पता उल्लेख नहीं करवा कर धारा 28 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। अन्त में अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर दण्डित करने का निवेदन किया।

इसके पश्चात आरोप पूर्व साक्ष्य में डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक के कथन लेखबद्ध किये गये और पक्षकारान की बहस चार्ज सुनकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाया जाने पर उसे दिनांक 26-10-05 को अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b) (ii) एवं धारा 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया समझाया गया, उसने आरोप इन्कार कर प्रकरण में अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन साक्ष्य में पी०ड० 1 डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक पी०ड० 2 ओम प्रकाश पी०ड० 3 बाबूलाल पी०ड० 4 डा० जी०पी० माथुर के बयान लेखबद्ध किये गये एवं दस्तावेज साक्ष्य में निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी० 1 फार्म नंबर 16 प्रदर्श पी० 2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दीगोद के अधिकारी की मुलजिम की अनुपरिस्थिति बायत रिपोर्ट प्रदर्श पी० 4, इश्यू चाउंचर प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी० 5 एवं 6, ब्रदर्स फार्मा प्रा०लि० जयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को जारी बिल प्रदर्श पी० 7, डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक मुख्यालय कोटा की रिपोर्ट प्रदर्श पी० 8, स्टाक रजिस्टर उच्चिकृत उप केन्द्र ग्राम नयागॉव प्रदर्श पी० 9, इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी० 10 रटाक रजिस्टर उच्चिकृत उप केन्द्र ग्राम नयागॉव की प्रति प्रदर्श पी० 11 एवं 12, मुलजिम मदनलाल को दिया गया निरीक्षण एवं जक्ती के संबंध में नोटिस प्रदर्श पी० 13, जवाब प्रदर्श पी० 14, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदर्श पी० 15, निरीक्षक नियुक्त करने का नोटीफिकेशन प्रदर्श पी० 16, परिवाद प्रदर्श पी० 17, स०ला०अ० के पैरवी का प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी० 18 को प्रदर्शित करवाया गया।

इसके पश्चात अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० लिये गये तो उसने जक्ती उसके सामने किया जाना स्वीकार किया है एवं नया गॉव में उसके सामने स्टाक रजिस्टर की जाँच करना और स्टाक इन्चार्ज होना स्वीकार किया। जवत्शुदा औषधियों का बिल पेश नहीं करना और लाईसेंस नहीं था इस तथ्य को स्वीकार किया है। फार्म नंबर 16 में साइन करना और रिपोर्ट पर साइन करना स्वीकार किया है, यकी तथ्य गलत बताये हैं।

बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2/1/02  
औषधि नियंत्रक अधिकारी  
कोटा (राज०)



12.03.14  
मुख्य प्रतिकर  
कोटा

मुख्य प्रतिकर  
कोटा  
29 MAR 2014

इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि-

- (1) क्या मुलजिम ने दिनांक 28-2-95 को समय 12-30 पी०एम० पर ग्राम दीगोद में बिना औषधि अनुज्ञापत्र के 9 प्रकार की औषधियाँ जिनका विवरण फार्म नंबर 16 में है, का संग्रह अपनी दुकान में कर एवं विक्रय वितरण हेतु प्रदर्शित की ?
- (2) क्या मुलजिम ने उक्त दिनांक समय एवं स्थान पर मुलजिम से जब उक्त औषधियाँ किसी व्यक्ति से कय किया, प्राप्त किया, का नाम पता औषधि निरीक्षक को नहीं बताया ?

उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी । दौराने बहस में मुलजिम ने स०लो०अ० ने कथन किया है कि पत्रावली में आयी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपण अपराध सन्देह से परे सिद्ध होता है । अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे ।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने निम्नलिखित तर्क पेश किये हैं :-

- (1) मुलजिम के विरुद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को सर्वप्रथमात्ता यह सिद्ध करना है कि मुलजिम ने उससे जब्तशुदा औषधियों को विक्रय करने के लिए तैयार हो ? और यह तथ्य कि विक्रय हेतु रखा है यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है । केवल मात्र औषधियों को अपने पास रखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपने तर्क के समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त ए०आई०आर० 1979 एस०सी० 564 मो० शब्बीर बनाम महाराष्ट्र राज्य

पेश किया है ।

- (2) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि इस न्यायालय को प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है बल्कि माननीय सेशन न्यायालय को इसका अधिकार है ? धारा 32/36 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बार कस्त है ?

- (3) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि जो औषधियाँ मुलजिम से मिली हैं वे सभी बाजार में आसानी से मिल जाती है एवं सभी के घरों में होती हैं । उक्त औषधियों का फर्द जब्ती में 9 नंबर की देवाई Metoclopramide जो मुलजिम से जब्त होना बताया जा रहा है । यह देवाई मुलजिम ने अपनी पत्नी को अस्पताल में दिखया था और उसकी पत्नी को यह देवाई इश्यू हुई थी जिसका एन्ट्री आउटडोर रजिस्टर प्रदर्श डी० 1 है एवं प्रिश्किप्शन प्रदर्श डी० 3 है ।

- (4) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि हस्तगत प्रकरण में मुलजिम के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई Sanction प्राप्त नहीं हुई थी । अतः बिना Sanction के मुलजिम के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपने तर्क के समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त 2012 कि०ला० जनरल 4115 राज्य बनाम मो० रफीक

पेश किया है ।

- (5) विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह तर्क पेश किया है कि सेम्पल लेते समय धारा

2/188  
साक्षी नियंत्रण अधिकारी  
कोटा

29 MAR 2014

मुख्य प्रतिनिधिकारि  
बि. एवं सेशन न्यायालय, कोटा

12.03.14  
कम-5, कोटा (राज.)

23 (1) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की पालना करना अनिवार्य है किन्तु इस प्रकार प्रकरण में इसकी पालना नहीं की गयी है ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपने समर्थन में सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त :-  
2011 (2) क्रि०ला०रि० (राज०) 1531  
वैकुंथा पांडुरंग प्रभू एवं अन्य बनाम राज० राज्य

पेश किया है ।

उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली में आयी साक्ष्य का अवलोकन किया गया । पत्रावली में अभियोजन पक्ष ने जो साक्षीगण पेश किये हैं उसमें डा० मनोज कुमार औषधि निरीक्षक को बतौर पी०डो 1 परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तो उन्होंने अपनी साक्ष्य में कथित किया है कि दिनांक 28-2-95 को औषधि निरीक्षण पर तैनात था । उस दिन दिन में साढ़े 12 बजे के करीब डा० जी०पी० माथुर एवं डा० के०एल० कुमट के साथ ग्राम दीगोद कोटा स्थित दुकान का निरीक्षण करने पहुँचे थे । इस पर मदनलाल सुमन हाजिर अदालत की उपस्थिति एवं दो स्थानीय साक्षीगण ओमप्रकाश स्वामी एवं बाबूलाल सेनी की मौजूदगी में निरीक्षण किया था । दुकान में दाखिल होने से पूर्व उन्होंने एक समस्त व्यक्तियों ने जामातलाशी स्वयं की ली थी । उक्त दुकान में औषधियों का स्टाक पाया गया । पूछने पर श्री मदनलाल ने औषधियों बाबत कोई अनुज्ञापत्र पेश नहीं किया था । मेडिकल प्रेक्टिशनर का प्रमाण पत्र पेश किया था । इस प्रकार उनके पास औषधियों का कोई विधि सम्मत कारण नहीं था । पूछने पर बताया था कि यह दवाईयों बेचने के लिए हैं । इन दवाईयों में एक दवाई राजकीय सप्लाय की होने का सन्देह था । उक्त औषधियों को फार्म नंबर 16 पर जप्त किया गया । समस्त कार्यवाही के पश्चात मुलजिम ने विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया ।

पी०डो 2 के रूप में ओम प्रकाश को परीक्षित करवाया जो फर्द जक्ती का साक्षी है जो पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हो गया है ।

पी०डो 3 बाबूलाल भी फर्द जक्ती का साक्षी है और यह भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हो गया है ।

पी०डो 4 डा० जी०पी० माथुर हैं, जिन्होंने कथन किया है कि दिनांक 28-2-95 को दीगोद में मदनलाल सुमन मेल ग्रेड द्वितीय कम्पाउण्डर के साथ वह एवं सी०एम०एण्ड एच०एस० कोटा के साथ दुकान का निरीक्षण किया गया था । समस्त कार्यवाही सी०एम०एण्ड एच०एस० उनके सामने की थी । समस्त दवाईयों दुकान में थी और सरकार की थी एवं वहाँ पायी गयी थी । इन दवाईयों को रखने बाबत मदनलाल के पास कोई अनुज्ञापत्र या लाईसेंस नहीं था । मिली हुई दवाईयों का विवरण फार्म नंबर 16 में अंकित है । रिपोर्ट प्रदर्श पी० 1 बनायी थी, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं ।

अतः अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये साक्षीगण में सबसे अधिकतर साक्षी पी०डो-1 डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक हैं, जिन्होंने अपने बयान प्रदर्श पी० 17 में यह तथ्य अंकित किया है कि डा० जी०पी० माथुर मुख्य चिकित्सक अधिकारी एवं डा० के०एल० कुमट की उपस्थिति में अभियुक्ता की दुकान का निरीक्षण किया था और जिसके यहाँ पर औषधियों का स्टाक पाया गया था जिसका विवरण प्रदर्श पी० नंबर 16 में अंकित है ।

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिनिधिकार  
ला एवं संमान न्यायालय, कोटा

29 March 2011

S. Red

इस सन्दर्भ में प्रदर्श पी० 2 फार्म नंबर 16 का अवलोकन करके जोर देकर उल्लेख है कि दिनांक 28-2-95 को मदनलाल सुमन की दुकान सुल्तानपुर राई ग्राम जिला कोटा का निरीक्षण किया गया था और उसमें नौ तरह की दवाईयाँ मिली थी और इनमें से ज्यादा इंजेक्शन्स थे और एक इंजेक्शन Metoclopramide इंजेक्शन था जिसकी कुल संख्या 10 थी और राजस्थान सरकार अंकित था। उक्त फार्म नंबर 16 पर मुलजिम ने अपने हस्ताक्षर जो से एच स्वीकार किये हैं, किन्तु इस संबंध में अपने बयान मुलजिम में अंकित किया है कि उसने साइन किये थे लेकिन पढ़ा नहीं था।

मेरी राय में केवल मात्र यह कह देने से कि बिना पढ़े मुलजिम द्वारा साइन किये हैं यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने नहीं पढ़ा हो क्योंकि यह अविवादित है कि मुलजिम एक कम्पाउण्डर हैं। यदि शिक्षित व्यक्ति द्वारा बिना पढ़े साइन किये जाते हैं तो इस संबंध में जिम्मेदार होगा।

इसके अलावा अपने बयान मुलजिम में स्वयं मुलजिम ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसके सामने दिनांक 28-2-95 को डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक डा० जी०पी० माथुर, एवं डा० के०एल० कुम्ट के सामने औषधियाँ जब्त हुई थी और मुलजिम के अनुसार उसने यह औषधियाँ अपने परिवार के लिए रखी थी। अतः इन परिस्थितियों में फार्म नंबर 16 एवं मुलजिम के बयान मुलजिम से यह अविवादित है कि मुलजिम से फार्म नंबर 16 में अंकित दवाईयाँ जब्त हुई हैं।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने दौराने बहस यह कथन किया कि केवल मात्र औषधियों को स्टोक करना धारा 27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में अपराध में नहीं है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त ए०आई०आर० 1979 एस०सी० 564 मो० शब्बीर बनाम महाराष्ट्र राज्य

में उल्लेख किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अवलोकन किया। उक्त प्रकरण के तथ्य हस्तगत प्रकरण से बिल्कुल भिन्न हैं। उपरोक्त प्रकरण में रेल्वे स्टेशन से 17 प्लास्टिक कंटेनर में 17000 व्हाइट कलर टेबलेटस बरामद हुए थे। हस्तगत प्रकरण में मुलजिम की दुकान से औषधियाँ बरामद हुई हैं और इस फर्द जिले में मुलजिम ने स्वीकार किया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त ए०आई०आर० 1974 एस०सी० 517 सावंतराज बनाम महाराष्ट्र राज्य पूर्ण रूप से चस्पा होता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

"Storage, even though for short spells and on ad hoc basis, and without intent to sell at a certain place but as part of the sales business, comes within scope of storage for sale in section 18 (c) and R. 62.

इसके अलावा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त ए०आई०आर० 1985 पेज 26 राज्य बनाम पूरणलाल में यह अंकित किया है कि :-

"Section 27- it would make a mockery of the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 or similar other provisions if large scale stock of prohibited drugs or

औषधि नियंत्रण अधिकारी  
कोटा (राज.)

सत्य प्रतिलिपि  
मुख्य प्रतिनिधिकार  
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा  
29 MAR 1985

other articles which were kept without any valid licence and yet the accused are allowed to go scot free on the fallacious assumption that the stock found from the shop was not meant for sale. If that view was accepted as correct it would become impossible to proceed against any one. In such a case wherever a raid takes place when shop is closed the accused will always be able to get away because it would be said that the stock was not meant for sale. After all people do not for fun of it keep scores of bages or vials full of drugs or goods for which a valid licence is required. Interpretation of law must be attune to the general and natural conduct of an individual."

इसके अलावा सेक्शन 18 (c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में offer संशोधन कर दिनांक 1-2-1983 को जोड़ा गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि सेल होना नहीं है। औषधि को सेल के लिए offer करना भी सेक्शन 18 (c) औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम में आता है।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये पी०डी० 1 डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक एवं समस्त दस्तावेजों से अभियोजन पक्ष मुलजिम के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है और पी०डी० 1 डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक के बयानों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

इस संबंध में माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सम्माननीय न्यायिक इन्स्पेक्टर ड्रग्स, केसेज 1976 पेज 78 द पब्लिक प्रोसीक्यूटर आन्ध्र प्रदेश बनाम महावीर प्रसाद एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

(E) Drugs and Cosmetics Act, 1940 - Drugs Inspector cannot be called partisan

एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि

"ड्रग इन्स्पेक्टर की साक्ष्य पर अविश्वास करने का क्या कारण है क्योंकि वह अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान कार्यवाही करता है। अतः उसके द्वारा की गयी कार्यवाही पर शक नहीं किया जा सकता।"

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने ऐसा कोई तर्क पेश नहीं किया है कि ड्रग इन्स्पेक्टर पी०डी० 1 डा० मनोज कुमार त्रिपाठी की कोई रंजिश मुलजिम से रही हो। अतः सिद्ध नहीं है वहाँ ड्रग इन्स्पेक्टर पी०डी० 1 डा० मनोज कुमार त्रिपाठी कार्यवाही एवं बनायी गयी फर्द जंती पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता मुलजिम द्वारा पेश किया गया तर्क कि फार्म नंबर 16 में 9 नंबर पर जो औषधि Metoclopramide अंकित है वह मुलजिम ने अपनी पत्नी को अस्पताल में दिखाने गया था जिसका प्रिशिकषात्र प्रदर्श डी० 1 है रजिस्टर में एन्ट्री प्रदर्श डी० 1 है, इसलिए यह औषधि मुलजिम मदनलाल के घर में थी।

मेरी राय में केवल मात्र इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि औषधि केवल उनकी पत्नी के लिए रखी गयी हो। इसकी कुल संख्या 6 बतायी गयी है चूँकि यह इन्जेक्शन है। अतः इन्जेक्शन अस्पताल में ही दिये जाते हैं, न कि घर पर।

इसके अलावा ऐसा कोई प्रावधान विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने पेश नहीं किया है कि कम्पाण्डर अपने घर पर इन्जेक्शन दे सकता हो और मुलजिम मदनलाल कम्पाण्डर

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिका है, इसलिए यह औषधि मुलजिम मदनलाल के घर में थी।

बिला एवं सैफर न्यायालय, काट

29 MAR 2014



5 फीट

S. (ed)

था एवं राजकीय सेवा में था ।

जहाँ तक अन्य दवाईयों 1 लगायत 8 का प्रश्न है ? इस सन्दर्भ में प्रदर्श पी० 10 2 फार्म नंबर 16 का अवलोकन किया गया । इसके बावत एक नोटिस मुलजिम को प्रदर्श पी० 13 दिया गया था जिसका जवाब मुलजिम ने प्रदर्श पी० 14 दिया है । उक्त जवाब में भी फार्म नंबर 16 में अंकित दवाईयों 1 लगायत 8 के बारे में यह अंकित है कि यह औषधियाँ उसे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं के अनुसार अलग-अलग समय पर खरीदी गयी थी । उनके बिल उसके पास नहीं है ।

अतः The Drugs and Cosmetics Act, 1940 के section 18 (A) में मुलजिम है कि उससे जो औषधियाँ जब की गयी थी वह उसने कहीं से खरीदी थी यह प्रकरण में मुलजिम यह बताने में असमर्थ रहा है ।

जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का यह तर्क कि इस न्यायालय को प्रकरण का सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है ?

मेरी राय में यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि The Drugs and Cosmetics Act, 1940 के section (32) (2) के अनुसार :-

32. Cognizance of offences - (2) No Court inferior to that of ( a Metropolitan Magistrate or of a Judicial Magistrate of the first class ) shall try an offence punishable under this chapter.

जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का यह तर्क कि प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य है ?

मेरी राय में यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि The Drugs and Cosmetics Act, 1940, section (32) दिनांक 10-3-2009 को संशोधित किया गया था और उसके पश्चात् The Drugs and Cosmetics Act में अध्याय संख्या 4 के तहत जो अपराध है वह माननीय न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने योग्य हैं ।

हस्तगत प्रकरण वर्ष 2009 से पूर्व का है एवं The Drugs and Cosmetics Act, 1940 के section 18 (A) में मुलजिम से जो बरामदगी है वह The Drugs and Cosmetics Act में जो संशोधन उससे पहले का होने के कारण पूर्व का जो The Drugs and Cosmetics Act है उसके तहत प्रकरण गर्वन होगा और The Drugs and Cosmetics Act 1940 के सेक्शन 32 के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार है ।

जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का तर्क कि बिना स्वीकृति लिये मुलजिम के विरुद्ध पेश किया गया है ?

मेरी राय में यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि The Drugs and Cosmetics Act, 1940 में स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि कन्ट्रोलिंग आथोरिटी से इसका प्रावधान है ।

The Drugs and Cosmetics Act, 1940, section (32) के सन्दर्भ में माननीय

इन्तहाय उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त सरदार बसकरण सिंह बनाम राज्य 1974,

2/88  
आपसी नियंत्रण अधिकारी  
काठमांडू

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिका के विरुद्ध पेश किया गया है ?  
जिला एवं सेशन न्यायालय, काठमांडू

29 MAR 2014



कि०ला०जनरल 728 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

" (2) यह कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 32 के तहत प्रसंज्ञान लेने हेतु अगर अभियोजन स्वीकृति लिये जाने की अनिवार्यता सिद्ध उसका स्पष्ट उल्लेख होता जैसा कि इसी अधिनियम के Chapter IV-A के तहत वर्गीकृत आयुर्वेदिक सिद्धा एवं यूनानी ड्रग्स के मामले में प्रसंज्ञान लेने हेतु स्पष्ट तौर पर लिखा है ।"

हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श पी० 15 के जरिये औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर में मुलजिम मदनलाल के विरुद्ध डा० मनोज कुमार त्रिपाठी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं ।

जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता मुलजिमका यह कथन कि सेक्शन 23 (1) अधिनियम प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की पालना नहीं की गयी है ।

मेरी राय में केवल मात्र इस आधार पर अभियोजन कहानी पर सन्देह नहीं किया जा सकता क्योंकि हस्तगत प्रकरण में कोई सेम्पल नहीं लिया गया है बल्कि सम्पूर्ण औषधियाँ मुलजिम से जब्त हुई थी, उनको सील किया गया था । यह तर्क मानने योग्य नहीं है । अतः इन परिस्थितियों में यह तर्क मानने योग्य नहीं है ।

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का तर्क कि स्वतंत्र साक्षीगण पी०ड० 2 ओम प्रकाश पी०ड० 3 बाबूलाल दोनों पक्षदोही घोषित हो गये हैं । अतः यह सिद्ध नहीं है कि मुलजिम दोषी रहेगा ?

मेरी राय में यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि पी०ड० 2 ओम प्रकाश पी०ड० 3 बाबूलाल दोनों ने फार्म नंबर 16 प्रदर्श पी० 2 एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी० 1 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है । उनके हस्ताक्षर जबरदस्ती कराये गये हों या उनकी पी०ड० 1 डा० मनोज कुमार त्रिपाठी औषधि निरीक्षक से कोई रजिश्तरी हो यह सिद्ध नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह तथ्य निर्विवाद है कि मुलजिम के कब्जे से फार्म नंबर 16 प्रदर्श पी० 2 में अंकित औषधियाँ जब्त की गयी थीं जिन्हें उसको पास नहीं था और वह यह बताने में असमर्थ रहा है कि उन्होंने कहाँ से कय किया । अतः अभियोजन पक्ष मुलजिम मदनलाल के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा (ii) एवं धारा 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम सन्देह से परे सिद्ध पूर्णतः सफल रहा है । मुलजिम मदनलाल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 18(c) एवं धारा 18 (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है ।

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिका  
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

29 MAR 2014

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम - 5 कोटा

सजा के विषय पर सुना गया ।

विद्वान स०लो० ने निवेदन किया है कि मुलजिम के विरुद्ध सिद्ध हुए अपराध को प

2/10/14  
औषधि नियंत्रक राजस्थान  
कोटा (राज.)

नजर रखते हुए उस उचित दण्ड से दण्डित किया जावे ।

अधिवक्ता मुलजिम ने निवेदन किया है कि प्रकरण वर्ष 1998 से लंबित है और 17 साल की लंबी अन्वीक्षा भुगत रहा है । अतः इन परिस्थितियों में मुलजिम को परीक्षा का लाभ प्रदान किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया । यह तथ्य निर्विवाद है कि पत्रावली पर मुलजिम के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्ध का कोई प्रमाण नहीं है, परन्तु अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है ।

#### दण्डादेश

अतः अभियुक्त मदनलाल सुमन आत्मज गेंदीलाल जाति सुमन निवासी सुल्तानपुर ग्राम एवं पोस्टदीगोद जिला कोटा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b) (i) (A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाकर अपराध अन्तर्गत धारा 18(c)/27(b) (ii) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/-रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 18(A)/28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500/-रु० अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अभियुक्त मदनलाल अदम अदायगी अर्थदण्ड की स्थिति में 15-15 दिवस का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेंगा । सभी सजायें साथ-साथ चलीगी । मुलजिम द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में धिमायी गयी अवधि मूल सजा में से गणना की जावेगी । मुलजिम का सजा वारण्ट बनाया जावे । मुलजिम को नकल निर्णय दिनांक 12-3-14 की जावे । मुलजिम के उपस्थिति बाबत जमानत मुद्दालके निरस्त किये जाते हैं । जब्तशुदा माल बाद मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे ।

12.03.14  
(सुनियता के.पी.पी.)  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम - 5 कोटा

निर्णय आज दिनांक 12-3-14 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

सत्य प्रतिलिपि  
मुख्य प्रतिनिधि  
विद्या एवं वैभव न्यायालय, कोटा  
29 MAR 2014

12.03.14  
(सुनियता के.पी.पी.)  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम - 5 कोटा

2.1.14  
सुनियता के.पी.पी.